News सिटी चीफ
वर्ष-15, अंक-166
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

आज का विचार

ज़िन्दगी में संघर्ष की उतनी ही जरूरत है जितनी नए पत्ते आने के लिए पतझड़ की...

बिहार सिटी चीफ

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

बिहार, शनिवार 21 सितम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

जेई को स्मार्ट मीटर लगाना पड़ा महंगा

गांव वालों ने सिखाया ऐसा सबक कि दौड़कर भागे बिजली ऑफिस

(औरंगाबाद)। पुलिस की मौजूदगी में स्मार्ट मीटर लगाने गए जेई एवं विद्युत कर्मियों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। कुटुंबा विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के जेई प्रिया कंचन कुमार निराला व उनके साथ रहे विद्युत कर्मी घायल हो गए। मामला कुटुंबा थाना क्षेत्र के खुशिहालपुर गांव की है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग की टीम गुरुवार को स्मार्ट मीटर लगाने गांव पहुंची थी। ग्रामीणों के घर में लगे पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था। लगभग 10 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका था। इसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सूचना पर जेई प्रिया कंचन कुमार निराला पहुंचे तो ग्रामीणों ने उनके साथ बदसलूकी की। घटना के बाद आक्रोशित बिजली कर्मियों ने गांव का कनेक्शन छुड़ा दिया। जेई द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष अक्षयवर सिंह ने दूसरे दिन पुलिस बल मुहैया की बात कह कर जेई को वापस भेज दिया। दूसरे दिन शुक्रवार को जेई के साथ 112 की टीम को गांव भेजा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार करते हुए जेई व विद्युत कर्मियों पर हमला बोल दिया। कुछ देर तक तो पुलिस मूकदर्शक बनी रही। बाद में समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए।

जेई के बयान पर थाना में प्राथमिकी कनीय विद्युत अभियंता ने थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी कराया है। पुलिस को दिए आवेदन में ग्रामीण संजय मेहता, बाबूलाल मेहता, दिलकेश मेहता, मुन्ना मेहता, चंदन मेहता, सिनेश मेहता, अनिल मेहता समेत अन्य ग्रामीणों को आरोपित किया है। जेई ने पुसि को बताया कि गुरुवार को मानव बल दीपक कुमार, ओम प्रकाश यादव, दक्ष खलासी कमलेश राम व इंटील स्मार्ट एजेंसी के जोनल मैनेजर पुरुषोतम कुमार के साथ गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे। ग्रामीणों ने सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न किया। इस कार्य के लिए दूसरे दिन पुलिस से सहयोग ली गई लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट की। उधर ग्रामीणों ने जेई व उनके साथ स्मार्ट मीटर लगाने गए कर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली कर्मी पुरुष की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे थे। ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत कर्मियों द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के एवज में रुपये की वसूली की जा रही थी।

घर में लगे पुराने मीटर को हथौड़ी से तोड़ा जा रहा था। मना करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। विरोध करने पर बिजली कर्मियों ने गांव के ट्रांसफार्मर का कनेक्शन छोड़ा दिया जिस कारण हंगामा हुआ है। ग्रामीणों के आवेदन पर संजय कुमार मेहता, इंदु देवी, चंद्रावती देवी, वीरेंद्र मेहता, बालकेश मेहता, दिलकश मेहता समेत 50 से अधिक ग्रामीणों का हस्ताक्षर है।

बिहार में बाढ़ से दहशत, अब तक 5 की मौत

पटना समेत 11 जिलों के 5.35 लाख लोग प्रभावित

गंगा, गंडक, घाघरा, सोन समेत कई नदियों में उफान के बाद बिहार में बाढ़ से दहशत का माहौल बना हुआ है। बाढ़ का पानी राज्य के 11 जिले की 259 ग्राम पंचायतों में फैल गया है। इससे करीब 5.35 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। अभी तक बाढ़ के पानी में डूबने से पांच लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक भोजपुर और चार सारण जिले के हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को संबंधित जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जलस्तर पर लगातार निगरानी रखने और सभी पीड़ितों पर राहत बचाव कार्य पहुंचाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के बीच पॉलिथिन शीट का वितरण किया जा रहा है।

अब तक करीब 35 हजार शीट बांटी जा चुकी हैं। चार राहत शिविर और 66 रसोई केंद्र का संचालन शुरू कर दिया गया है। 4250 राशन पैकेट भी बांटे गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 13 यूनिट तैनात की गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए 971 नावों का परिचालन शुरू किया गया। चिकित्सकीय सहायता के लिए सात बोट एंबुलेंस चलाई जा रही हैं।

गंगा से सटे निचले इलाकों पर ज्यादा असर गंगा नदी से सटे इलाकों पर बाढ़ का ज्यादा असर देखा जा रहा है। पटना, भोजपुर, वैशाली, सारण, बेगूसराय जिले ज्यादा प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बक्सर के तीन प्रखंड की पांच पंचायतों के 1780 लोग, भोजपुर के चार प्रखंडों की 43 पंचायतों की 70 हजार 234 आबादी, सारण के छह प्रखंड की 29 पंचायतों के 76 हजार 19 लोग, वैशाली के छह प्रखंड की 31 पंचायतों के 94 हजार 600 लोग, पटना के आठ प्रखंडों की 43 पंचायतों के 93 हजार, समस्तीपुर के तीन प्रखंडों की 18 पंचायतों के 7600, बेगूसराय के आठ प्रखंडों की 29 पंचायतों के 45 हजार, मुंगेर के छह प्रखंडों की 22 पंचायतों के 81363, खगड़िया के चार प्रखंडों की 21 पंचायतों के 19770 लोग, भागलपुर के चार प्रखंडों की 8 पंचायतों की 1192 आबादी प्रभावित हुई है।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्देश दिया कि लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाओं के साथ ही चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाए। जिन क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, वहां बोट एंबुलेंस चलाई जाय। बच्चों, वृद्धजन एवं गर्भवती महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जाय। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से पानी निकलने पर ब्लीचिंग पाउडर का तुरंत छिड़काव कराएं। पीड़ितों के बीच आवश्यकतानुसार राशन पैकेट का वितरण कराएं। सामुदायिक रसोई का संचालन शुरू किया जाय। पशुओं के लिए दवा-चारा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए जाएं।

पेपर लाने के लिए समय देगी सरकार लेकिन नहीं रुकेगी डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की मुहिम

पटना, बिहार में पंचायत से अंचल तक जमीन का मालिकाना हक दिखाने वाले कागजात के लिए जूझ रहे लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने संकेत दिया है कि जमीन मालिकों को दस्तावेज को जमा करने के लिए समय दिया जाएगा लेकिन जमीन सर्वे का काम नहीं रुकेगा। बिहार भूमि सर्वे में लोगों को आ रही परेशानियों और विपक्षी दलों के हमले के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार की सरकार जमीन सर्वे के लिए कोई समय सीमा तय किए बिना धीरे-धीरे काम को आगे बढ़ाएगी। राज्य के भूमि सुधार मंत्री व भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि जमीन मालिकों को स्वामित्व के लिए खुद का घोषणा पत्र जमा करने के लिए और समय दिया जाएगा।

दिलीप जायसवाल ने कहा- हमने लोगों की परेशानियों की समीक्षा की है। इसके लिए समय सीमा बढ़ाई जाएगी। कुछ दिन में सरकारी आदेश निकल जाएगा। हमने चल रहे काम की समीक्षा की है और सब ठीक चल रहा है। पूरी कवायद का मकसद है कि डिजिटल जमीन रिकॉर्ड के साथ सही लोगों के लिए जमीन का विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। मंत्री ने हालांकि ये साफ कर दिया कि सरकार इससे पीछे नहीं हटने वाली है। उन्होंने कहा कि लैंड माफिया जान-बूझकर भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं लेकिन वो काम नहीं करने वाला।

नवादा में महादलितों की बस्ती में जमीन कब्जा के मकसद से दबंगों द्वारा आगजनी की घटना के बाद मंत्री का बयान महत्वपूर्ण है। नवादा शहर से महज दो किलोमीटर दूर इस बस्ती की जमीन को दबंग लैंड सर्वे से पहले कब्जा कर लेना चाहते हैं ताकि इसे अपना दिखा सकें। हालांकि नवादा के डीएम ने कहा है कि 1995 से इस जमीन के मालिकाना हक का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने मई में विवादित जमीन की जांच का आदेश भी दिया था क्योंकि इसका मालिक कौन है, ये साफ नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये सरकारी जमीन थी जिसे किसी ने सरकारी अधिकारियों की मदद से अपने नाम करवा लिया होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कौन है। भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जमीन के मालिकाना हक को लेकर मुकदमे की खबर उन्होंने भी पढ़ी है जबकि कुछ लोग कुछ और बात कर रहे हैं। सिंह ने नवादा डीएम से रिपोर्ट मांगी है और कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि इस समय क्या स्थिति है। नवादा की घटना अलग तरह की है लेकिन ये आखिरी हो, ऐसा नहीं है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और कब्जा की शिकायत पूरे राज्य में है। ऐसे में जमीन के सर्वे से गैर कानूनी तरीके से जमीन कब्जा किए लोगों में बेचैनी और छटपटाहट है। कई परिवार में जमीन दादा या परदादा के नाम पर ही है जो अलग समस्या है। बिहार में बहुप्रतीक्षित जमीन सर्वे का लक्ष्य राज्य के लगभग 45 हजार गांवों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना है। सरकार ने इसके लिए 25 जुलाई 2025 की समय सीमा तय की है जो विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पूरी हो सकती है। अगर समय से पहले चुनाव हो गए तो यह प्रक्रिया चुनाव से पहले अधूरी भी रह सकती है। जमीन के कागज तैयार करने में जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आ रही हैं जिसके जवाब में सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमीन के कागज तैयार करने की सुविधा का प्रचार कर रही है। लेकिन गांवों में इस सुविधा का उपयोग कितने लोग कर पाए हैं, ये कहा नहीं जा सकता। नीतीश सरकार के एजेंडा पर लैंड सर्वे काफी समय से था। राज्य में जमीन का विवाद क्राइम का सबसे बड़ा कारण है, ये एनसीआरबी के आंकड़ों से भी स्पष्ट हुआ है। जमीन विवाद को खत्म कर कानून-व्यवस्था को ठीक करना नीतीश का मकसद है। एनसीआरबी का ताजा डेटा बताता है कि बिहार में 60 प्रतिशत हत्याएं जमीन के लिए हुईं। एक अफसर ने कहा कि इस सर्वे से सरकार को भी राज्य में फैली अपनी जमीन का हिसाब मिल जाएगा। सरकार को भूमिहीनों को देने के लिए जमीन चाहिए, बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन चाहिए। जमीन अधिग्रहण में जमीन का कागज के बिना मुआवजा देना मुश्किल है। जेडीयू के एक सीनियर नेता ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश खुद जमीन सर्वेक्षण की समीक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को भी फीडबैक मिल ही रहा होगा। ये पता ही था कि ये चुनौतीपूर्ण है लेकिन बिहार में यह समय की मांग है। जेडीयू नेता ने 2016 से बिहार में लागू शराबबंदी की वजह से सरकार के राजस्व में कमी का इशारा करते हुए सीएम की तारीफ की और कहा कि नीतीश इन चुनौतियों से निबटने के लिए ही जाने जाते हैं।

एनआईटी बिहटा के छात्रावास में आंध्र प्रदेश की छात्रा ने किया सुसाइड

कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने की नारेबाजी

पटना- बिहार में पटना के बिहटा स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की एक छात्रा ने संस्थान के छात्रावास में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पटना के बाहरी इलाके बिहटा में स्थित एनआईटी की यह शाखा में पढ़ रही छात्रा आंध्र प्रदेश की निवासी थी। पुलिस ने घटनास्थल से एक 'सुसाइड नोट भी बरामद किया है।

छात्रावास के कमरे में पंखे से लटका मिला शव

पटना पुलिस द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, शुक्रवार रात करीब सवा 10 बजे पुलिस को एक फोन कॉल के जरिए बताया गया कि एक छात्रा ने अपने छात्रावास के कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसका शव लटका हुआ पाया...छात्रा को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने छात्रा का नाम नहीं बताया है।

घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद

बयान में कहा गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छात्रा आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और उसके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है और मौके से सभी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं तथा आगे की जांच जारी है। बयान में कहा गया है कि घटना का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। छात्रा की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में एकत्र एनआईटी छात्रों संस्थान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।

समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव, मुखिया को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा

समस्तीपुर बिहार में अपराध चरम पर है। रोजाना हत्या, लूट और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला समस्तीपुर जिले से सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की। जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के हलई पुलिस आउट थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्रवार देर रात वनवीरा पंचायत के मुखिया नारायण शर्मा को अपराधियों ने मार दी। बताया जा रहा है कि मुखिया नारायण शर्मा डिहिया पुल के पास एक दाह संस्कार कार्यक्रम में गए हुए थे। इस दौरान अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। वह जिले के मोरवा प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे। वहीं, मुखिया नारायण शर्मा की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने आज सुबह से ही जिले के हलई बाजार के पास समस्तीपुर-जन्दाहा मार्ग को जाम कर यातायात को बाधित कर दिया है। प्रदर्शनकारी हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं।

एनआईटी पटना में आंध्र प्रदेश की छात्रा ने किया सुसाइड

छात्रों का देर रात हंगामा

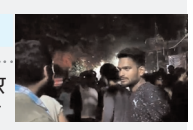

पटना, बिहार की राजधानी पटना में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) में एक छात्रा ने शुक्रवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। यह घटना एनआईटी के बिहटा कैंपस स्थित हॉस्टल की है। छात्रा पल्वी रेड्डी (19) आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी आत्महत्या की खबर जैसे एनआईटी पटना कैंसप तक पहुंची, वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया। बिहटा थानेदार राजकुमार पांडे ने बताया कि पुलिस को रात करीब 10.30 बजे सूचना मिली कि बीटेक सेकंड ईयर की छात्रा ने हॉस्टल में सुसाइड कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि हॉस्टल प्रबंधन छात्रा को लेकर अस्पताल चला गया। जहां उसे डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। हंगामे को लेकर कैंपस में भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई। एनआईटी के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने आरोप लगाए कि कॉलेज प्रशासन की ओर से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पल्वी के फंदे पर लटके हुए पाए जाने के बाद हॉस्टल की छात्राओं को उनके कमरों में बंद कर दिया गया।